राजस्थान राज्य

बनाम

किशन लाल

10 मई 2002

[न्यायमूर्ति, वाई.के. सभरवाल और न्यायमूर्ति, बिशेश्वर प्रसाद सिंह]

दंड संहिता, 1860 :

धारा 376–बलात्कार–ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को दोषसिद्धि–उच्च न्यायालय द्वारा सजा में कमी–अपील पर, माना गया: चूंकि उच्च न्यायालय ने सजा कम करने के लिए कोई पर्याप्त या विशेष कारण दर्ज नहीं किया है, इसलिए उच्च न्यायालय का आदेश उचित नहीं है। ,

बलात्कार––अभियोजन पक्ष का संस्करण–सच्चाई–संदेह–इस संभावना को बढ़ाना कि अभियोजन पक्ष सहमति देने वाला पक्ष था–इसलिए प्रतिवादी संदेह का लाभ पाने का हकदार है और इस प्रकार बरी कर दिया गया।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:~~

धारा 373(3) – की प्रयोज्यता – सजा की अपर्याप्तता के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील – बरी करने की याचिका – उठाना – न्याय के गर्भपात को रोकने के उद्देश्य से, सर्वोच्च न्यायालय ऐसे अनुरूप सिद्धांतों को अपना सकता है ताकि ऐसी अपीलों के निपटान के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया बनाई जा सके और प्रतिवादी को ऐसी याचिका उठाने की अनुमति दी जा सके– भारत का संविधान; अनुच्छेद, 136.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, पीड़िता का पति और जीजा कहीं चले गए थे और वह घर में अकेली थी।

घर; उसकी भाभी पास के घर में सो रही थी। रात को जब आरोपी उसके घर आया तो उसने उसे पहचान लिया और आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच उसका पति और देवर घर लौट आए, जिन्हें उसने सारी कहानी सुनाई। आरोपी ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पति, देवर और ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और घर में बांधकर रखा और पुलिस को सौंप दिया। अभियोजक ने अगली सुबह एफआईआर दर्ज कराई। प्रतिवादी–अभियुक्त पर आईपीसी की धारा 376 और 457 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया और मुकदमा चलाया

गया। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी–अभियुक्त को आरोपों का दोषी पाया और उसे क्रमशः 7 साल और 1 साल के कठोर कारावास और जुर्माना भरने की सजा सुनाई। अपील पर, उच्च न्यायालय ने सजा को घटाकर आरोपी द्वारा पहले ही काट ली गई अवधि तक कर दिया। इसलिए राज्य द्वारा यह अपील।

अपीलकर्ता–राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की सजा को पहले ही काट ली गई अवधि तक कम करके कानूनी गलती की है, जो आईपीसी की धारा 376 के स्पष्ट प्रावधानों के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं थी; दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377 भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील पर लागू नहीं होती है; और अभियोजन पक्ष बलात्कार में सहमति देने वाला पक्ष नहीं था।

प्रतिवादी–अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, सीआरपीसी की धारा 377 में निहित सिद्धांतों के अनुरूप सिद्धांत लागू कर सकता है।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए

अभिनिर्धारित किया: 1. आईपीसी की धारा 376 के प्रावधान में प्रावधान है कि न्यायालय, फैसले में उल्लिखित पर्याप्त और विशेष कारणों से, सात साल से कम अवधि के कारावास की सजा दे सकता है। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने पहले से ही भुगती गई अवधि तक सजा को कम करने के लिए पर्याप्त या विशेष कारण दर्ज नहीं किए हैं, सिवाय इसके कि प्रतिवादी वर्ष 1988 से हिरासत में था और ऐसे मामलों में न्यायालयों ने उदार रुख अपनाया है। ऐसा बयान उन पर्याप्त और विशेष कारणों के विवरण का उत्तर नहीं देता है जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाना आवश्यक था। इसलिए, यह पेटेंट है कि प्रतिवादी की सजा को कम करने का आदेश अवैध है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

2. इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य ने सजा की वैधता को चुनौती देने वाली अपील को प्राथमिकता दी है। इस अर्थ में यह अपर्याप्तता के आधार पर सज़ा बढ़ाने की अपील नहीं है। हालाँकि, यह भी उतना ही सच है कि यदि सजा को अवैध पाया जाता है और रद्द कर दिया जाता है और उचित सजा दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप सजा में वृद्धि होगी। राज्य की अपील को अनुमति दिए जाने का एकमात्र परिणाम सजा को बढ़ाना होगा और इसलिए, अपील वास्तव में प्रतिवादी की सजा को इस आधार पर बढ़ाने के लिए है कि उसके खिलाफ लगाई गई सजा कानून के अनुसार नहीं है, और नहीं पर्याप्त, क्योंकि यह कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा से कम है।

3. विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या इस न्यायालय को सजा बढ़ाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर अपील पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377(3) में निहित सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। यह प्रश्न अब एकीकृत नहीं है और प्रतिवादी सीआरपीसी की धारा 377(3) के अनुरूप सिद्धांतों को अपनाकर अपील में बरी होने के लिए बहस करने का हकदार है।

यूपी राज्य बनाम धर्मेंद्र सिंह और अन्य, एसटी (1999) एससी 207, पर भरोसा किया।

4.1. यह आश्चर्य की बात है कि जब आरोपी रात में पीड़िता के घर सी में दाखिल हुआ और हालांकि पीड़िता का साला और उसकी पत्नी केवल 20–25 फीट की दूरी पर सो रहे थे, पीड़िता शोर नहीं मचा सकी। उनका ध्यान आकर्षित करें.

ऐसा प्रतीत होता है कि जब आरोपी उसके साथ यौन संबंध बना रहा था तो अभियोक्ता कोई प्रतिरोध नहीं कर रही थी। बचाव पक्ष का कहना है कि जब उसका पति कमरे में आया तभी उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसका प्रतिवाद राज्य द्वारा यह कहकर किया जाता है कि प्रतिवादी अपने साथ एक चाकू लेकर आया था और उसने चाकू से अभियोक्ता को धमकी दी थी और इसलिए, डर के कारण, वह न तो अलार्म बजा सकती थी और न ही प्रतिवादी का विरोध कर सकती थी; इसके अलावा आरोपी ने उसके मुंह में जबरदस्ती रूमाल ठूंस दिया था। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि चाकू को मुकदमे में प्रदर्शित नहीं किया गया है, न ही ऐसा प्रतीत होता है कि इसे जांच के दौरान जब्त किया गया था। सामान्य स्थिति में चाकू अभियोक्त्री के घर से बरामद किया जाना चाहिए था। चाकू की जब्ती न होना अभियोजन पक्ष की बात की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करता है कि प्रतिवादी ने धमकी के तहत पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए थे।

5. मामले की इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त द्वारा पीड़िता की सहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा अवैध थी, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर, प्रतिवादी संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1996 की आपराधिक अपील संख्या 516।

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.4.91 से एस.बी. सी.आर.एल. 1990 का ए नंबर 371.

अपीलकर्ता की ओर से रणजी थॉमस और जावेद महमूद राव।

प्रतिवादी की ओर से आलोक भचावत (ए.सी.)।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

बिशेश्वर प्रसाद सिंह, जे. विशेष द्वारा यह अपील! राजस्थान राज्य द्वारा दी गई छुट्टी राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर, जयपुर पीठ, जयपुर के 26 अप्रैल, 1991 के एस.बी. मामले के निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है। 1990 की आपराधिक अपील संख्या 371।

आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध का दोषी ठहराते हुए उसकी सजा को पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि तक कम कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब आक्षेपित निर्णय पारित किया गया तो प्रतिवादी लगभग 22 वर्ष की सज़ा काट चुका था। इससे पहले विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बारां ने प्रतिवादी को आईपीसी की धारा 376 और 457 के तहत अपराध का दोषी पाया था। धारा 376 आईपीसी के तहत 7 साल का सश्रम कारावास और 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 500 रुपये, डिफ़ॉल्ट पर छह महीने का साधारण कारावास। उन्होंने उसे | की सज़ा भी सुनाई आईपीसी की धारा 457 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 200, डिफ़ॉल्ट पर 3 महीने का साधारण कारावास।

चूंकि प्रतिवादी का हमारे सामने कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए हमने श्री आलोक भचावत, वकील से न्याय मित्र के रूप में हमारी सहायता करने का अनुरोध किया। उन्होंने न्यायालय को बहुत अच्छी सहायता प्रदान की है। शुरुआत में राज्य के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के खिलाफ पारित सजा को पहले से ही पूरी की गई अवधि तक कम करके कानून में स्पष्ट रूप से गलती की है, जो आईपीसी की धारा 376 के व्यक्त प्रावधान के मद्देनजर अस्वीकार्य है, जो कि आरोपी को खोजने पर अनिवार्य है। आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध का दोषी, इस प्रकृति के मामले में, आरोपी को एक अवधि के लिए सजा दी जाएगी जो 7 साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन या 10 साल तक बढ़ सकती है और हो सकती है। जुर्माना भी देना होगा. हालाँकि, धारा 376 के प्रावधान में यह प्रावधान है कि अदालत फैसले में उल्लिखित पर्याप्त और विशेष कारणों से सात साल से कम अवधि के कारावास की सजा दे सकती है। फैसले में फाड़े गए न्यायाधीश ने सजा को पहले से

ही पूरी की गई अवधि तक कम करने के लिए कोई पर्याप्त या विशेष कारण दर्ज नहीं किया है, सिवाय इसके कि प्रतिवादी वर्ष 1988 से हिरासत में था और ऐसे मामलों में अदालतों ने उदार रुख अपनाया है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा बयान "पर्याप्त और विशेष कारणों" के विवरण का उत्तर नहीं देता है जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाना आवश्यक था। विद्वान न्यायमित्र उच्च न्यायालय के सजा को पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि तक कम करने के आदेश के समर्थन में कोई तर्क पेश नहीं कर सके। इसलिए, यह पेटेंट है कि प्रतिवादी की सजा को कम करने का आदेश अवैध है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

हालाँकि, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि राजस्थान राज्य ने विशेष अनुमति द्वारा, आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है: प्रतिवादी को पहले ही पूरी हो चुकी अवधि के लिए सजा देना और अपील की अनुमति का प्रभाव यह है कि प्रतिवादी की सज़ा को कम से कम 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को प्रतिवादी को बरी करने के लिए बहस करने की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि विशेष अनुमति द्वारा अपील, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, सजा को बढ़ाने के लिए एक अपील है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 377(3) में निहित सिद्धांत को लागू कर सकता है जो कि प्रदान करता है। जब सजा की अपर्याप्तता के आधार पर सजा के खिलाफ अपील दायर की जाती है, तो आरोपी कारण बताते हुए खुद को बरी करने या सजा कम करने की गुहार लगा सकता है।

राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि राज्य द्वारा की गई अपील सजा को बढ़ाने के लिए अपील नहीं है, बल्कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को रद्द करने के लिए है, जो स्पष्ट रूप से अवैध है और प्रावधान के स्पष्ट आदेश के विपरीत है। . इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य ने सजा की वैधता को चुनौती देने वाली अपील को प्राथमिकता दी है। इस अर्थ में यह अपर्याप्तता के आधार पर सजा को बढ़ाने की अपील नहीं है। हालाँकि, यह भी उतना ही सच है कि यदि सजा को अवैध पाया जाता है और रद्द कर दिया जाता है और उचित सजा दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप सजा में वृद्धि होगी। राज्य की अपील की अनुमति दिए जाने का एकमात्र परिणाम सजा को बढ़ाना होगा और इसलिए, हमारा विचार है कि अपील वास्तव में प्रतिवादी की सजा को इस आधार पर बढ़ाने के लिए है कि उसके खिलाफ लगाई गई सजा का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह कानून के अनुरूप है, और पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा से कम है।

अगला प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या इस न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377(3) में निहित सिद्धांतों को सजा बढ़ाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष अपील पर लागू करना चाहिए।

राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 377 केवल उच्च न्यायालय के समक्ष सजा बढ़ाने की अपील पर लागू होती है। संदर्भ में यह धारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सजा की वृद्धि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील पर लागू नहीं होती है।

विद्वान न्याय मित्र ने ठीक ही कहा कि यह प्रश्न अब पूर्णांक नहीं रह गया है। यूपी राज्य में बनाम धर्मेंद्र सिंह और अन्य: जेटी 1999 (7) एससी 207 इस न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 377(3) पर विचार किया और इस प्रकार देखा: –

"इस धारा के अवलोकन से पता चलता है कि यह प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष होता है और यह इस न्यायालय पर लागू नहीं होता है जब संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सजा बढ़ाने की अपील की जाती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संहिता की धारा 379 के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, आपराधिक मामलों में इस न्यायालय में अपील संहिता के तहत प्रदान नहीं की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में अपील संहिता के तहत वैधानिक अपील के समान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत यह न्यायालय अपील की कोई नियमित अदालत नहीं है, जहाँ कोई अभियुक्त अधिकार के रूप में जा सकता है। यह एक असाधारण क्षेत्राधिकार है जो केवल असाधारण मामलों में ही प्रयोग किया जा सकता है जब यह न्यायालय संतुष्ट हो कि उसे न्याय के गंभीर या गंभीर गर्भपात को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, जैसा कि साक्ष्य की सराहना में केवल त्रुटि से अलग है। इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, यह न्यायालय नीचे की अदालतों पर लागू प्रक्रिया के नियमों से बाध्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार 4 केवल अपने विवेक से सीमित है (देखें निहाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1965) एससी 26)। मामले को देखते हुए, हमारी राय है कि संहिता की धारा 377(3) संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील पर लागू नहीं होती है।

इसका मतलब यह नहीं है कि यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील के निपटान के लिए एक प्रक्रिया तैयार करते समय संहिता की धारा 373(3) सहित संहिता में पाए गए सिद्धांतों के अनुरूप सिद्धांतों के प्रति अनभिज्ञ रहेगा। इस न्यायालय में आपराधिक अपीलों के निपटान के लिए लागू सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के अलावा, न्यायालय ऐसे समान सिद्धांतों को भी अपनाता है। संहिता में ताकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर प्रक्रिया को "निष्पक्ष प्रक्रिया" बनाया जा सके।

इसलिए, इस न्यायालय ने उत्तरदाताओं को यूपी राज्य द्वारा दायर अपील में बरी करने के लिए बहस करने की अनुमति दी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377 (3) में पाए गए अनुरूप प्रावधान को अपनाकर सजा में वृद्धि के लिए।

विद्वान न्याय मित्र ने प्रस्तुत किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय ने न्याय के गर्भपात को रोकने के उद्देश्य से विवेकपूर्ण मिसाल कायम की है और यही कारण है कि कुछ मामलों में जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कोई भी अभियुक्त संभव है, उस निर्णय का लाभ सह–अभियुक्त को दिया गया, भले ही उसने इस न्यायालय में अपील याचिका के माध्यम से आदेश को चुनौती न दी हो। (देखें राजा राम और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य: [1994] 2 एससीसी 568 और दांडू लक्ष्मी रेड्डी बनाम राज्य आंध्र प्रदेश: [1999] 7 एससीसी 69।)

विद्वान न्याय मित्र ने प्रस्तुत किया कि यह उचित मामला है जहां उन्हें प्रतिवादी को बरी करने के लिए बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए और हमने ए को उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी। पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की सहायता से, हमने अपने सामने रखे गए रिकॉर्ड का अध्ययन किया है और हमने मुकदमे में जांचे गए गवाहों की गवाही की सावधानीपूर्वक जांच की है।

श्रीमती द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अभियोजन शुरू किया गया था। धुलीबाई, अभियोजक, पी.एस. 8 दिसंबर, 1985 की सुबह छीपा बड़ोद। उन्होंने बताया कि कल रात उनके पति छीतरलाल, पीडब्लू.11 अपने भाई राम दयाल, पीडब्लू.2 के साथ रामलीला देखने गए थे। वह घर में अकेली थी. उसके साले की पत्नी दूसरे घर में सो रही थी। उसके पति ने रामलीला देखने जाते समय घर की बाहर से कुंडी लगा दी थी। रात के करीब 11–12 बजे उसकी नींद खुली, जब किसी ने दरवाज़ा खोला। उसने प्रतिवादी किशनलाल को पहचान लिया और उससे पूछा कि वह क्यों आया है। उसने कहा कि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने आया था। उसने चिमनी (तेल का दीपक) बुझा दी। वह रोने लगी लेकिन

प्रतिवादी ने उसके मुँह में कपड़े का एक टुकड़ा डाल दिया। उसने उसके स्तन दबाये और हाथापाई में उसके ब्लाउज के 2 बटन टूट गये। इसके बाद उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिर उसने कहा कि वह उसे रुपये देगा। 20 और फोलिया को भी इसी काम के लिये बुलाऊंगा। लगभग उसी समय उसका पति और देवर घर लौट आये। उसने यह कहानी अपने पति को सुनाई। घर में मौजूद प्रतिवादी किशनलाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पति, देवर और गांव के कुछ अन्य लोग उसके पीछे भागे। प्रतिवादी पत्थरों पर गिरकर घायल हो

गया। हालाँकि, उसे पकड़ लिया गया और घर में बाँध कर रखा गया। चूंकि वे रात में पुलिस स्टेशन नहीं आ सके, इसलिए वे अगली सुबह मामले की रिपोर्ट करने आए।

मामले की जांच अभियोजन गवाह 7 श्यामलाल, थाना प्रभारी, पुलिस थाना छीपाबड़ौद द्वारा की गई। उन्होंने साइट प्लान तैयार किया, अभियोक्त्री और प्रतिवादी के कपड़े जब्त कर लिए जिन्हें रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के लिए भेजा गया। उन्होंने प्रतिवादी किशनलाल को 12 दिसंबर, 1985 को गिरफ्तार कर लिया, भले ही उन्हें 8 दिसंबर, 1985 को उनके सामने पेश किया गया था क्योंकि इस अवधि के दौरान उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। आरोपी के सिर और शरीर पर चोटें थीं.

गवाहों को दिए गए सुझावों से यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी–अभियुक्त किशनलाल का बचाव अभियोजन पक्ष का गवाह था। 12 धुलीबाई, अभियोजन पक्ष एक सहमति वाली पार्टी थी। पंच गवाह अभियोजन गवाह 4 और अभियोजन गवाह 6 और अभियोजन गवाह 18 जैसे औपचारिक गवाहों के अलावा, जिन्होंने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में लेख ले गए थे, अभियोजन पक्ष ने अभियोजक के पति छितरलाल से पीडब्लू 11 के रूप में पूछताछ की है। और अभियोक्ता श्रीमती. धुलीबाई अभियोजन गवाह के रूप में।12 और चार गवाह, अर्थात्, कन्हियालाल, पीडब्लू.1; रामदयाल, अभियोजन गवाह.2 और राधाकिशन, अभियोजन गवाह.3 और बालचंद, अभियोजन गवाह.4, जो घटना के तुरंत बाद अभियोजन पक्ष के घर पहुंचे. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभियोजन पक्ष गवाह 11 अभियोजन पक्ष के पति छीतरलाल पहले आए थे उसके बाद अभियोजन पक्ष का गवाह 2 रामदयाल 2–3 मिनट बाद आया। अभियोजन गवाह 3 और अभियोजन गवाह 4 एक ऐसे चरण में आए जब प्रतिवादी को पकड़ लिया गया और बांध दिया गया।

प्रतिवादी के बचाव को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन गवाह 11 और अभियोजन गवाह 12, अर्थात्, पीड़िता के पति छीतरलाल और स्वयं अभियोजक के साक्ष्य की गंभीरता से जांच करना आवश्यक होगा। छीतरलाल, अभियोजन गवाह 11 ने कहा कि वह आरोपी किशनलाल को जानता था। घटना की रात जब वह घर लौटा तो उसने घर के दरवाजे खुले पाए और 2–4 साल की बच्ची के रोने की आवाज सुनी। उसकी पत्नी धूलीबाई ने उसे बताया कि किशनलाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। उस समय किशनला! घर में था. उसकी आवाज सुनकर किशनलाल भागने लगा लेकिन उसने पीछा कर उसे घर में ही पकड़ लिया। दूसरे दिन सुबह वह अपनी पत्नी के साथ थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई।

जिरह में उसने कहा कि वह पहले उसके घर आया और उसका भाई रामदयाल, अभियोजन गवाह 2, 2–3 मिनट बाद आया। प्रतिवादी किशनलाल दूसरे गाँव का था और उसके गाँव और प्रतिवादी के गाँव के बीच की दूरी

लगभग एक मील है। वह अक्सर अपने गांव आता रहता था. उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने आरोपी के साथ मारपीट की थी और कहा कि पत्थरों पर गिरने के कारण उन्हें चोटें आई थीं। उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि आरोपी को घर के बाहर पकड़ा गया था. उसने रात में ही सरपंच को बुला लिया था और उसके अलावा बड़ी संख्या में लोग भी आये थे जो रामलीला देखने गये थे। उनकी पत्नी ने उन्हें प्रतिवादी के कुकर्मों के बारे में बताया था। अगली सुबह करीब 9 से 10 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई गई. उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आरोपी पहले भी उनके घर आते थे। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने उन्हें यह नहीं बताया कि आरोपी ने उनसे कहा था कि वह उसी काम के लिए किसी अन्य व्यक्ति को लाएंगे और इसके लिए उन्हें भुगतान किया जाएगा। उनके घर और उनके भाई के घर के बीच की दूरी करीब 30 फीट है. उन्होंने आगे कहा कि जब उनकी पत्नी के साथ यौन उत्पीड़न किया गया तो वह रो रही थीं। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या आरोपी ने उसकी सहमति से ऐसा किया है या उसकी सहमति के बिना तो उसने जवाब दिया कि उसकी सहमति नहीं थी और यह जबरदस्ती किया गया था।

श्रीमती धुलीबाई, अभियोजन गवाह 12, अभियोजक ने कहा कि वह आरोपी को जानती थी। घटना की रात उसका पति बाहरी दरवाजे पर कुंडी लगाकर रामलीला देखने चला गया था। वह अपने 5–6 महीने के बच्चे के साथ सो रही थी और उसका साला लगभग 20–25 फीट की दूरी पर अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में सो रहा था। रात करीब 10–12 बजे आरोपी उसके घर में घुस आया, जिसे उसने चिमनी के पास से पहचान लिया। यह पूछे जाने पर कि वह रात में क्यों आया था, आरोपी ने जवाब दिया कि वह उसके साथ संभोग करने आया था। उसने उसके ब्लाउज के बटन तोड़ दिये. उसने उसके स्तनों को दबाया और उसके स्तनों पर अपने नाखूनों से खरोंचें दीं। इसी बीच बच्चा उठकर रोने लगा. उसने उसे थप्पड़ मारा. आगे कहा गया है कि जब वह चिल्लाई तो उसने उसके मुंह में रूमाल डाल दिया. जब वह चिल्लाती रही तो आरोपी ने उसे चाकू दिखाया और धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो वह उसे चाकू मार देगा। उसने यह भी कहा कि उसने उससे कहा कि वह उसे रुपये देगा। 20 लेकिन पैसे नहीं दिए। उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच उसका पति आ गया। उसके पति ने उससे पूछा कि क्या उसने उसे बुलाया है, तो उसने नहीं में जवाब दिया। आरोपी भागने लगा तो उसके पति ने उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसका देवर रामदयाल भी आ गया। उन्होंने आरोपी को पकड़कर बांध दिया. अगली सुबह वे थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई.

अपनी जिरह में उसने स्वीकार किया कि वह आरोपी को घटना से करीब 6 महीने पहले से जानती थी। लेकिन उसने इस बात से इनकार कर दिया कि आरोपी अक्सर उसके घर आता था। उसके मुंह में डाला गया रूमाल पुलिस ने जब्त कर लिया। उसकी चिकित्सकीय जांच की गई।

उसने फिर कहा कि जब उसका पति घर के अंदर आया, तो आरोपी वास्तव में उसके साथ संबंध बना रहा था। आरोपियों के अंदर आने के बाद दरवाजे के कुंडी खुले रह गए थे। [वह उसका पति था जिसने आरोपी को उसके शरीर से हटा दिया था। रामदयाल, PW.2 बाद में आये। आरोपी को उसके पति ने घर में ही पकड़ लिया। उसने इस बात से इनकार किया कि उसे पत्थरों के पास पकड़ा गया था और कहा कि पुलिस ने जांच के दौरान जो बयान दर्ज किया था कि वह पत्थरों से टकराने के बाद पत्थरों पर गिर गया था, गलत था। उनके मुताबिक आरोपी को किसी ने पीटा नहीं था. उसने इस बात से इनकार किया कि यह सब उसकी सहमति से हुआ था और उसने आरोपी को बुलाया था। हालाँकि, उसने स्वीकार किया कि आरोपी ने उससे कहा था कि वह उसे रुपये देगा। 20 और वह रु. उसी उपकार के लिए फुलिया 20 रुपये देगी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि घर के अंदर आ रहे लोगों को देखकर ही उन्होंने चिल्लाना शुरू किया था. उनके अनुसार, प्रतिवादी को बांधने के बाद, उसने पत्थरों से टकराना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसे चोटें आईं, उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसके पति ने उसके स्तनों पर खरोंचें पैदा की थीं।

परिवार स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी, अभियोजन गवाह 9, जिन्होंने अभियोजक की जांच की, ने कहा कि उन्हें स्तनों पर 1 सेमी के दो खरोंच पाए गए जो परीक्षा के 24 घंटों के भीतर हुए थे। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि धूलीबाई के साथ बलात्कार हुआ था. उन्होंने आरोपी की जांच भी की थी और पाया था कि वह यौन संबंध बनाने में सक्षम है. हालाँकि, उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता ने अपने पति के साथ संभोग किया है और निजी अंगों पर चोटें संभोग के दौरान हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोक्ता के स्तनों पर खरोंचें खुद को पहुंचाई गई हो सकती हैं।

यह आश्चर्य की बात है कि आरोपी रात में घर में दाखिल हुआ और हालांकि पीड़िता का बहनोई और उसकी पत्नी केवल 20–25 फीट की दूरी पर सो रहे थे, पीड़िता उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अलार्म नहीं बजा सकी। ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता आरोपी को जानती थी और इसीलिए उसने पहला सवाल यह पूछा कि वह रात में क्यों आया था। इस पर आरोपी ने जवाब देते हुए कहा कि वह उसके साथ यौन संबंध बनाना चाहता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ–साथ धुलीबाई, अभियोक्त्री और छीतरलाल, पीडब्लू.11 के बयान में इस तथ्य का उल्लेख है कि आरोपी ने उसे रुपये की पेशकश की थी। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए 20 रुपए दिए

और यह भी कहा कि फुलिया भी उसे उसके साथ संभोग करने के लिए इतनी ही रकम देगी। इस पर अभियोजक द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है। इससे यह आभास होता है कि अभियोक्त्री और प्रतिवादी काफी घनिष्ठ थे। मामले की दूसरी आश्चर्यजनक बात यह है कि पीड़िता के पति ने घर में घुसने के बाद सीधे आरोपी का पीछा नहीं किया। उसने पहले अपनी पत्नी से पूछा कि क्या उसने उसे बुलाया था, और उसके यह कहने के बाद कि उसने उसे नहीं बुलाया था और उसने उसके साथ जबरन बलात्कार किया था, उसने प्रतिवादी का पीछा करना शुरू कर दिया और उसे पकड़ लिया। यह इस तथ्य को फिर से उजागर करता है कि पति को भी अपनी पत्नी की नापाक गतिविधियों के बारे में कुछ संदेह था, अन्यथा यह काफी अस्वाभाविक होगा कि एक पति, आरोपी को पकड़ने की कोशिश करने से पहले ही अपनी पत्नी से पूछे कि क्या उसने उसे बुलाया था , और क्या आरोपी ने उसकी सहमति से संभोग किया था।

मामले का एक और पहलू भी है. अभियोजक के अनुसार वह आरोपी के साथ संभोग कर रही थी तभी उसका पति आ गया। उसके अनुसार, यह उसका पति ही था जिसने आरोपी को उससे अलग कर दिया था। पीड़िता के पति ने ऐसा नहीं कहा है, हालांकि एक जगह उसने कहा है कि जब आरोपी उसके साथ संभोग कर रहा था तो उसकी पत्नी रो रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जब वह यौन संबंध बना रही थी तो अभियोक्ता कोई प्रतिरोध नहीं कर रही थी, तभी अचानक उसका पति अंदर आ गया।

कमरा। इसलिए, प्रतिवादी की ओर से तर्क दिया गया कि जब उसका पति कमरे में आया, तभी उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। राज्य की ओर से यह तर्क देने की मांग की गई थी कि प्रतिवादी अपने साथ चाकू लेकर आया था और उसने चाकू से पीड़िता को धमकी दी थी और इसलिए, डर के कारण, वह अलार्म नहीं बजा सकी या प्रतिवादी का विरोध नहीं कर सकी। !n इसके अलावा उसने उसके मुँह में ज़बरदस्ती रूमाल ठूंस दिया था। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि चाकू को मुकदमे में प्रदर्शित नहीं किया गया है, न ही यह जांच के दौरान जब्त किया गया प्रतीत होता है। यदि प्रतिवादी अपने साथ चाकू लाया था, और यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि उसे पकड़ लिया गया था घर के परिसर में ही, जाहिर तौर पर उसके पास कीइफ़ को फेंकने का कोई अवसर नहीं था। सामान्य प्रक्रिया में चाकू को अभियोक्त्री के गर्भगृह से बरामद किया जाना चाहिए था, चाकू की जब्ती न होना अभियोजन पक्ष की बात की सत्यता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है कि प्रतिवादी ने धमकी के तहत अभियोक्ता के साथ संभोग किया था।

मामले की इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त की संभावना। अभियोक्ता के साथ उसकी सहमति से यौन संबंध बनाने से इनकार नहीं किया जा सकता। जिन विशेषताओं को हमने ऊपर देखा है, वे प्रतिवादी के

बचाव की संभावना रखते हैं, और हम अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता के बारे में गंभीर संदेह मानते हैं कि आरोपी ने पीड़िता की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाए थे।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि प्रतिवादी संदेह का लाभ पाने का हकदार है। परिणामस्वरूप, इस अपील का निपटारा इस निष्कर्ष के साथ किया जाता है कि यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा अवैध थी, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि प्रतिवादी संदेह का लाभ पाने का हकदार है। इसलिए अपील खारिज की जाती है और प्रतिवादी को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है। प्रतिवादी के जमानत बांड उन्मोचित किये जाते हैं।

हमने श्री आलोक भचावत, अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है, जिन्होंने न्यायालय को उपयोगी सहायता प्रदान की है। उन्हें नियमानुसार न्यायमित्र को देय निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

अपील निस्तारित.

*श्री चंद्रकांत शुक्ला की देखरेख में कोपल यादव द्वारा अनुवादित।